4.00 p.m.

उपसभापति : आप यहीं बैठिए।

श्री प्रमोद महाजन : मैडम, मैं मीटिंग कर के आता हूं।

SHORT DURATION DISCUSSION

Growing unemployment in the country - *contd.*

[उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) *पीठासीन हुए*]

श्रम मंत्री (श्री शरद यादव) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, बेरोजगारी के विषय पर हुए शार्ट ड्यूरेशन डिस्कसन को माननीय सदस्यों ने बहुत मेहनत और शक्ति लगाकर कारगर बनाया। इस बहस में माननीय श्री जोशी, श्री जीवन राय, श्री के. रहमान खान, श्री ललित भाई मेहता, श्री एस. विद्युतलै विरुम्भी, श्रीमती विम्बा रायकर, श्रीमती सरोज दुबे, श्री दारा सिंह चौहान, श्री वी.वी. राघवन, श्री एस. निरैकुलथन, श्री शंकर राय चौधरी, श्री आर.एस. गवई, श्री राजीव शुक्ल, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री सतीश प्रधान और श्री मिर्जा अब्दुल रशीद ने भाग लिया।

उपसभाध्यक्ष जी, इस बहस को आप ने शुरू किया था और आप की अध्यक्षता में ही इस बहस का समापन हो रहा है। इस बहस में मेरे साथी रूरल डवलपमेंट मिनिस्टर ने भी भाग लिया और दो-तीन दिन तक हम सरकार के कई मंत्री बैठे रहे। हमारी कोशिश थी कि इस बहस का कारगर ढंग से हम जवाब दे सकें। लेकिन लगातार पांच दिन के बाद आज मौका मिला है और आज भी हमारे पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है कि इस बहस को मैं ज्यादा लंबा न करूं। मैं मानता हूँ कि यह सवाल बहुत अहम सवाल है और हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से इस विषय पर एक बार नहीं, कई बार जिक्र और चर्चा चली है। इस विषय पर माननीय सदन में माननीय सदस्यों ने जो यह बीमारी है और जो उसके उपाय हैं, उन सारी चीजों पर विस्तार से अपनी बात रखने का काम किया है। इसमें माननीय सदस्यों की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि बेकारी और बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं मानता हूँ कि जो पढ़े-लिखे नौजवान हैं और जो खासकर के श्रम करने वाले लोग हैं उनके बीच में गांव-देहात से लेकर शहरों तक बेकारी और बेरोजगारी बढ़ी है, आबादी भी उस हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। यह चिंता का विषय है, मैं इस बात को मानता हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर आपसे चर्चा शुरू होकर, कैलाश जोशी जी से चर्चा शुरू होकर बाकी माननीय सदस्यों ने भी अपनी बातों को रखा। इसमें चाहे रूरल एम्पलायमेंट की बात हो या अरबन एम्पलायमेंट की बात हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार की बात हो या अशिक्षित बेरोजगार की बात हो, इसकी बाबत कैसे रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं इनके लिए

रचनात्मक और कारगर तरीकों से कैसे लोगों को काम मिले, इस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। सबसे पहले सवाल आया कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, हमारा कृषि का उद्योग है, उस पर हमारी आबादी की सबसे बड़ी संख्या निर्भर करती है, उसी में काम करती है, इसलिए इस सेक्टर पर जितना अधिक ध्यान दिया जाएगा, उतने रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि हम हिन्दुस्तान की आजादी के 54 वर्ष का लेखाजोखा देखें तो हमें सबक मिलता है कि हमने जहां माइग्रेशन बढ़ाया है और अगर इस तरफ हम देखेंगे तो पंजाब और हरियाणा में परिस्थितियां बदली हैं। जैसा माननीय सदस्यों ने सजेशन दिया खासकर इरीगेशन के मामले में, जो एक बड़ा अहम सवाल है, इसको बनाना चाहिए। चूंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, हमारी खेती बहुत बढ़िया है, हमारे मौसम छह हैं, हमारे यहां विंड एनर्जी है, हमारे यहां सोलर एनर्जी है, हमारे यहां हाइड्रो एनर्जी है, इन सारी चीजों पर हमें विचार करना है कि इनका हम किस तरह इस्तेमाल करें, कैसे इनका प्रबंधन करें ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें। जहां हमने वाटर मैनेजमेंट का किया, जहां हमने पानी का इंतजाम किया, उससे उस इलाके में हिन्दुस्तान की आजादी के इन 54 वर्षों में स्थिति और परिस्थिति काफी तेजी से बदली है। माइग्रेशन से लेकर सब तरह की चीजों को अगर हम देखें तो पर-कैपिटा इन्कम से लेकर सभी चीजों में गुणात्मक परिवर्तन आया है। अगर इधर चले जाएं तो निश्चित रूप से हम देखते हैं कि गैर-सिंचित क्षेत्रों में बहुत से उद्योग-धंधे पनपे हैं। इसका कारण है कि कोपरेटिव मूवमेंट जो है वह इधर बहुत पनपा है। माननीय सदस्यों का यह भी सुझाव था कि हमारे यहां जो मिनरल हैं, जो हमारे यहां एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग हैं उनका बड़े पैमाने पर हम विकास करने का काम करें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पूंजी कम है, लेकिन ह्युमन रिसोर्स ज्यादा है, जिसे हमें रोजगार में लगाना है। माननीय सदस्य जीवन राय जी का सजेशन था कि ऐसे रोजगार हमको लगाने हैं, जिनमें पूंजी के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे पास ह्युमन रिसोर्सेस ज्यादा है। ह्युमन रिसोर्सेस का ठीक से इस्तेमाल करने के लिए निश्चित तौर पर इस तरह हमें पूंजी निवेश करना है ताकि उससे अधिक रोजगार सृजन हो। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इस बहस को हम दो हिस्सो में बांट कर देखें ।

श्री बाल कवि बैरागी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री शरद यादव जी को बीच में टोकना नहीं चाहता था। आपने एक अच्छे अध्ययन के साथ इस बहस का उत्तर शुरू किया है, जिसमें खेती से अपनी बात शुरू की है। मैं सिर्फ एक जिज्ञासा आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ कि इसी सीट से पहले के श्रम मंत्री महोदय ने अपने एक उत्तर में बताया था, क्योंकि आपने खेती की बात की है इसलिए बता रहा हूँ, कि हमारे देश की समृद्धि में पहले खेतिहर मजदूर का योगदान 27 प्रतिशत था, वह इन दिनों में घटकर 14 प्रतिशत रह गया है, 13 प्रतिशत खेतिहर मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ी है। तो क्या कारण है कि इतना काम होने के बावजूद हमारा खेतिहर मजदूर सड़क पर आ गया है? बच्चों के सामने नए अनुभव हैं, नए आकाश हैं, नयी संभावनाएं हैं, नए अवसर हैं लेकिन एक अनपढ़ और अधेड़ व्यक्ति जब बेरोजगार होकर सड़क पर आ गया है तो उसके लिए हमारे पास रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, इसका अध्ययन करके आप अपने उत्तर में इसका समावेश करेंगे तो आपका उत्तर मैं संपूर्ण मानूंगा और आपको धन्यवाद दूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : वे बताएंगे, वे खुद किसान पुत्र हैं।

श्री शरद यादव : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सारे सदस्यों ने दो हिस्सों में अपनी बात रखी। एक बात तो उन्होंने यह रखी कि हमारे यहां जो संपदा है मिनरल्स से लेकर खेती तक, उसका हम बेहतर तरीके से इंतजाम करें। यह प्रबंध ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है और लोगों ने यह भी कहा कि वह जमीन पर नहीं जा पा रहा है। चाहे जो भी सरकारें रही हों, उन्होंने जितने भी इम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम चलाए हैं, वे जमीन पर नहीं उतर पाए। आप जानते हैं कि गांव से लेकर शहर तक हमने जितनी भी योजनाएं बनाईं, वे जमीन पर नहीं उतर पाईं। हम अच्छी योजनाएं बनाते हैं, उसमें धनराशि खर्च करते हैं जो रोजगार को पैदा करने का काम करती हैं लेकिन वे जमीन तक नहीं जा पा रही हैं, इस तरह की दो चिंताएं माननीय सदस्यों ने प्रकट कीं।

महोदय, बेरोजगारी का जो सवाल है उसके दो हिस्से हैं। सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि जो गांव का उद्योग है, वह अकेले एग्रीकल्चर का नहीं है। हिंदुस्तान की सदियों से परंपरा रही है, हिंदुस्तान की आज़ादी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है दस्तकारों का। पहले गांवों में दस्तकार थे, गांव संपूर्ण बाजार से कटे हुए थे, बाजार की जरूरत उनको नहीं थी। चाहे वह सुनार हो, लुहार हो, बढ़ई हो, तेली हो, बार्बर हो, यानी टोटल कम्युनिटी थी, वह कम्यून सिस्टम पर चलती थी, उसका बाजार से बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं था। मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट पापुलेशन दस्तकारी में लगी हुई है। आज भी हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट है, उसका एक-तिहाई हिस्सा दस्तकारों की बदौलत आता है। टूरिस्ट सिर्फ हमारे दस्तकारों की कला को देखने के लिए आते हैं। हमारे देश में गारमेंट का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, हमारे यहां आभूषणों का काम, हीरे तराशने का काम बहुत होता है, यानी हमारी अंगुलियों में सदियों से कमाल है। वे जो दस्तकार हैं, उनकी करीब 7 फीसदी आबादी रोजगार में लगी हुई है। उसके ऊपर हमने 54 बरस से ध्यान दिया और आज भी हम खादी ग्रामोद्योग के जरिए 400 करोड़ रुपए उसमें दे रहे हैं। उसमें खुद ही इतनी शक्ति है कि करीब 25 लाख लोग उसमें रोजगार में लगे हुए हैं और उसके बाजू में 30 लाख लोग दस्तकारी के धंधे में लगे हुए हैं।

हमारा जो खेती का धंधा है, वह सबसे ज्यादा आबपाशी से बनता है। आप तो जानते हैं, आप स्वयं उस इलाके से आते हैं जहां पहले इरिगेशन नहीं था, तवा नहर जब वहां आ गई तो मजदूर जो उत्पादन करने वाला आदमी है, उसका डेली वेजेज 70 रुपए, 60 रुपए या 80 रुपए हो जाता है। पहले पानी खेत में गया, इसके बाद सड़क गई, इसके बाद बिजली गई। आप कह रहे हैं कि गांवों में रोजगार खत्म हो गया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आबपाशी के इलाकों में रोजगार खत्म नहीं हुआ है। जिन इलाकों में हम पानी नहीं ले गए, इरिगेशन नहीं ले गए, उन्हीं इलाकों में बेकारी और बेरोजगारी बढ़ी है, उन्हीं इलाकों में गरीबी और लाचारी बढ़ी है, उन्हीं इलाकों में माइग्रेशन बढ़ा है। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी पानी था, जो विंड एनर्जी हमारे पास थी, जो सोलर ऐनर्जी हमारे पास थी, उसका उपयोग करने में बहुत पैसा लगता है, वह बहुत कैपिटल इंसेंटिव है। अकेले हिमालय से 3 बड़ी नदियां निकलती हैं - सिंधु नदी है, गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है और बाकी नदियों का अगर मैं जिक्र करूं तो परमात्मा ने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया है कि हिमालय जैसा दुनिया में कोई पहाड़ नहीं है जिससे इतनी नदियां

निकलती हों। लेकिन हमने उसको कभी टेप करने का काम नहीं किया और जहां कहीं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हिन्दुस्तान में 54 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, मैं मानता हूं और आपको याद होगा कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद पंचवर्षीय योजना में सब लोग अपने यहां बड़े-बड़े कारखाने ले गए। लेकिन प्रतापसिंह कैरो जो एक किसान का बेटा था उसने हिन्दुस्तान में पहली पंचवर्षीय योजना में पानी ले जाने का काम किया। भाखड़ा नांगल ले गए। आज भाखड़ा नांगल से पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और जो श्रीगंगानगर है उसकी क्या हालत है? वह आज देश को पूरा का पूरा खाना खिलाने का काम कर रहा है, यानी एक छोटा से इलाके ने -इरिगेशन से आपका सेस् बढ़ाने का काम किया है। तो आपने जो बात कही है मैं आंकड़ों में नहीं जाता लेकिन निश्चित तौर पर जान लीजिए कि आपका जो बुंदेलखंड है, चाहे आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे आपका छत्तीसगढ़ हो आप कितने ही कारखाने लगा लीजिए, हिन्दुस्तान में जो आधार कारखाना है, आधार धंधा है वह गांव हैं, खेत हैं, खलिहान हैं उसको मजबूत करने का काम किया है। सदस्यों ने इस पर बहुत अच्छी बहस की है। कैलाश जोशी जी ने और जीवन राय जी तथा सब ने जो शुरुआत की थी निश्चित तौर पर इस सदन के जो सदस्य हैं, हकीकत के बहुत करीब हैं, हकीकत के हम करीब हैं लेकिन हमारा सिस्टम, हमारी जो यह व्यवस्था है वह जमीन तक चीजों को ले जाने का काम नहीं कर रही है और यह प्रयास सब के जरिए हो सकता है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हिन्दुस्तान में इन मदों के ऊपर पैसा नहीं जा रहा है। इन मदों पर जो पैसा जा रहा है मैं उसका थोड़ा सा उल्लेख आपसे करना चाहता हूं। बेकारी और बेरोजगारी के लिए यदि हम इस पूंजी का ठीक से बेहतर इस्तेमाल करें तो बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने का काम एक सिलसिले से, एक तरीके से यानी मैं नहीं कहता हूं कि दो-चार सालों में, एक साल में सब समाप्त हो जाएगा, निश्चित तौर पर यदि इसको हम मजबूती से शुरू करें तो रास्ता बन सकता है और जैसे चीन मजबूत हुआ है वैसे हमारा देश भी मजबूती की तरफ बढ़ सकता है। 1993-94 में जो बिलो पावर्टी लाईन थी वह 36 परसेंट थे। इसमें गरीबी रेखा के नीचे जो लोग घटे हैं वह अकेले हमारी सरकार के चलते नहीं घटे हैं। कुछ रास्ता, कुछ चीजें पुरानी सरकार से लेकर अभी तक चालू हैं तो आज घट करके 1999-2000 में जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं वह 26 परसेंट हैं। निश्चित तौर पर गरीबी घटी है। लेकिन घटने का मतलब यह नहीं कि हम चिंता न करें, ऐसी बात नहीं है। यह देश दुनियां का बहुत बड़ा देश है। गरीबी में हम नम्बर वन आज भी हैं। लेकिन इस बात पर भी हम सबको सहमत होने की जरूरत है कि यदि अकेले पार्टी या सरकार के दायरे से हम लोग सोचेंगे जिस तरह से उपसभाध्यक्ष जी, आपने बहस को शुरू किया था कि यह मामला सब का है और आज तो दिल्ली में सरकार भले हमारी हो -नेशनल डेमोक्रेटिक एलॉएंस की लेकिन सूबे में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं और यह जो कार्यक्रम है खास करके एम्प्लोयमेंट जेनिरेशन का इसमें चाहे एम.पी. लेड फंड हो, चाहे दूसरी तरह के फंड हों यह सारे फंड स्टेट गवर्नमेंट के शू ही खर्च होते हैं। पर जो अंतिम आदमी है, जो झाड़ी मजदूर है, जो बनिहार है उसकी बेकारी और बेरोजगारी दूर नहीं होगी। हमारे यहां एक कहावत है कि : "पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो किस्मत के खेल।" इसी ने इस देश को बरबाद किया है। मैं आपको कहता हूं कि पढ़ने-लिखने वाले आदमी का रोजगार बाद में आता है, जो उत्पादन और मेहनत करता है उसका रोजगार पहले आता है। पहले उसका रोजगार आएगा तब पढ़े-लिखे लोगों का रोजगार आएगा। रूरल डवलपमेंट के मामले में जो एलोकेशन है यानी पिछले तीन साल से लगातार उतना ही है नौ हजार सात सौ पचास करोड़ रुपया। प्रधान मंत्री रोजगार योजना में दस हजार करोड़ था।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में पिछले साल 500 करोड़ रुपए था। इस साल उसको दो हजार पांच सौ करोड़ किया। वेस्ट एंड डवलपमेंट जिसके बारे में कैलाश जी ने और गुजरात के माननीय सदस्य मेहता जी ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि हिन्दुस्तान में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आबादी की यह हमारी बड़ी समस्या है। यह जो जमीन है वह घटती जा रही है, जोत घटती जा रही है, होल्डिंग स्मॉल होती जा रही है। तो इस पर पिछले साल पांच सौ करोड़ था। इसको बढ़ा करके दो हजार पांच सौ करोड़ किया है। हमने पिछले साल वेस्ट लैंड में 334 करोड़ रुपया दिया था और इस साल वेस्ट लैंड में हमने 900 करोड़ रुपये का 2000-2001 में इंतजाम किया है। यह जो नेशनल हाईवेज़ है, इसके मामले में बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने एक रास्ता बनाया है, देश को पूरी तरह से रेल से और रास्ते से ठीक से जोड़ना जरूरी है। इसलिए हाईवे रोड्स एंड नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम में 54 हजार करोड़ रुपये रखे हैं और यह पांच साल में करीब 2007 तक पूरा होगा और इस मद में कोई कमी नहीं आएगी। यह पैसा इस मद में जायेगा तो फिर इस देश के गिट्टी तोड़ने वाले, मिट्टी डालने वाले को रोजगार मिलेगा, पढ़ेलिखे नौजवानों को इससे रोजगार मिलेगा। रोड लिंकिंग टू दा पोटर्स हमने 4000 करोड़ रुपया रखा है जो कि अगले छह वर्षों में खर्च होंगे।

उपसभाध्यक्ष जी, रेलवे सेफ्टी में हमने 17 हजार करोड़ रुपया रखा है और इसको भी हम छह साल में फेजवाइज पूरा करेंगे। इससे अनएम्पलायमेंट घटेगा और बेकारी तथा बेरोजगारी की बीमारी से हमें निजात पाने का रास्ता मिलेगा। प्रधान मंत्री रोजगार योजना में वर्ष 1999 में 135 करोड़ रुपया दिया था और इसको 2000-01 में 200 करोड़ रुपया किया है। खादी विलेज इंडस्ट्री के लिए 2000-01 में 60 करोड़ रुपया दिया था लेकिन 2001-02 में हमने 87 करोड़ रुपया दिया है। एम्पलायमेंट जेनरेशन प्रोग्राम में पिछले साल 1999-2000 में 30 करोड़ रुपया था। इस साल हमने इसको 120 करोड़ रुपये किया है। हमने पावर सैक्टर के बजट के एलोकेशन को बढ़ाया है। पावर सैक्टर में पिछले साल 1999-2000 में 19157 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और इसको 2000-01 में बढ़ाकर 23645 करोड़ रुपये किया है। हैल्थ एंड फैमली वेलफेयर का जो बजट एलोकेशन हम लोगों ने किया है वह 1999-2000 में 4139 करोड़ रुपये का और 2000-01 में 4920 करोड़ रुपये का किया है। ह्यूमैन रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में जो बजट का एलोकशन हमने किया है वह 1999-2000 में 6375 करोड़ रुपये का और 2000-01 में 6910 करोड़ रुपये का किया है। पिछले साल एक्सपोर्ट ग्रोथ 21 परसेंट था, इस बार, मैं यकीनन मानता हूं कि वह बहुत तेजी से घटा है और उसके कारण 11 सितम्बर के बाद जो परिस्थिति देश में और दुनिया में बनी है उसके चलते इस बार का एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं हो पायेगा। हमारा ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप में होता था, उसमें गिरावट आई है, उसमें झटका आया है।

उपसभाध्यक्ष जी, मैंने जो आपके सामने आंकड़े रखे हैं, उनका मकसद इतना था कि रोजगार पैदा करने वाली जो मद हैं, उनमें सरकार ने अपनी ताकत और शक्ति को पूरी तरह से झौंका है, उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाई है और वह शक्ति इसलिए लगाई है कि जब तक हिन्दुस्तान के उत्पादन करने वाले लोगों की, बिना पढ़े-लिखे लोगों की, बनिहार की, खेत मजदूर की आमदनी नहीं बढ़ेगी तब तक हिन्दुस्तान की मजबूती नहीं हो सकती है। इसलिए यह एलोकेशन मैंने आपको बताया है। आपने जो निवेदन किया था कि ...(व्यवधान)...

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल) : मंत्री जी, तीन साल में तीन करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए कहा गया था, उसमें से कितने लोगों को नौकरी दी गई है? कृपया आप यह बता दीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) : मंत्री जी ने कितने आंकड़े गिनाएं हैं, वह तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। आपको तो मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। ...(व्यवधान)...

श्री शरद यादव : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे कहा गया है कि समय की कमी है। मैं अंत में यह निवेदन करना चाहता हूं।..

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप बोलिए, समय है।

श्री शरद यादव : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आम सहमति के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। मान लीजिए कि हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार का मामला है। जब तक सबके बीच में जागरूकता नहीं होगी, समाज में जागरूकता नहीं होगी और समाज में जागरूकता फैलाने का काम कौन करेगा? उस काम को तो राजनीतिक पार्टियां करेंगी। इस काम को हम सब लोगों को करना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष जी, हम सब लोगों की सरकारें हैं और कांग्रेस पार्टी की तो 11 सूबों में सरकार है, इतने सूबों में तो हमारी सरकारें भी नहीं हैं, स्टेट्स में जितने आपकी सरकारें हैं यानी कांग्रेस पार्टी जो आज अपोजीशन में बैठी है, यहां पर तो कोई अपोजीशन, मैं मानता नहीं हूं, लेकिन आपकी संख्या हमसे ज्यादा है। आप सब की सरकारें हैं और एम्पलायमेंट जेनरेशन का जो मामला है, इसकी सामर्थ्य व ताकत राज्य सरकारों में है और वही इसको जमीन पर ले जाती हैं क्योंकि उनके हाथ में पैसा जाता है। सभी सरकारों को मिलकर इस मामले में रास्ता बनाना चाहिए। इस आबादी के संबंध में हमें विचार करना होगा। कोड ऑफ कंडक्ट हर चीज़ के बारे में बन रहा है लेकिन आबादी के संबंध में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बन रहा। ...(व्यवधान)... उनके बस का भी नहीं है। एक बार आपने किया था, तब हार गये। नसबंदी के प्रोग्राम को आप इमरजंसी में न लाते तो हो सकता था कि हार जीत में फर्क पड़ जाता। महोदय, हिन्दुस्तान में जो आबादी है, यह बड़ी भारी समस्या है। अकेले बेकारी और बेरोज़गारी ही समस्या नहीं है। हमारे ह्यूमैन रिसोर्सिज़ को हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी कर लें तब भी आबादी जो तेजी से बढ़ रही है, इसके चलते हमारे जितने भी विकास के काम हैं, वह उनको पी जाती है, उनको खा जाती है। कोड ऑफ कंडक्ट हर चीज़ में बन रहा है, इस पार्लियामेंट में जो बहस होती है, उस बहस के ऊपर जो शरीफजादे हैं, वह बाहर कुछ का कुछ बोलते हैं। यहां सदन में जो चर्चा होती है, बहुत से लोग तो जानते भी नहीं हैं कि इस सदन में किस किस तरह की और दुनिया में किस तरह की बहस होती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहां तो बहुत कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है लेकिन आबादी के बारे में भी कोड ऑफ कंडक्ट हो और इलैक्शन कमीशन में यह प्रावधान हो कि हर पार्टी को अपनी चुनाव सभा में या मास रैली में जो भाषण करना है, उसमें उसको दो मिनट के लिए या पांच मिनट के लिए आबादी के ऊपर जरूर बोलना है कि परमात्मा ने जो धरती हिन्दुस्तान को दी है, वह सिर्फ 22 से लेकर 30 करोड़ लोगों की जिंदगी के लिए दी है, उसमें भी हिन्दुस्तान बंट गया है, उसको घटाने का भी काम होना चाहिए। निश्चित तौर पर जो मितव्ययी हैं जैसे बाजू में चीन है, वह लगातार आगे बढ़ रहा है। हम उसकी चर्चा तो करते हैं

लेकिन 54 वर्ष में खास करके जो ऑयल है, उसके मामले में हमारी जो दुर्गति है जिसके चलते यह पत्थर हमारे पैर पर पड़ा है, उसके चलते बेकारी और बेरोजगारी का समाधान कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी क्योंकि तेल जो है, वह बड़ी भारी समस्या है। महोदय, बाजू में चीन है। 45 साल वह साइकिल पर चला इसलिए आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें भी महात्मा गांधी ने सिखाया था कि मितव्ययी बनना चाहिए, फिजूलखर्ची बंद होनी चाहिए और डाउनसाइजिंग हो। डाउनसाइजिंग का जो जिम्मा हमें मिला है, उसमें हम पूरी ताकत लगाकर डाउनसाइजिंग करेंगे जिसका आपने उल्लेख करते हुए कहा। हमारी सरकार इसका प्रयास कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जिन सदस्यों ने डिबेट में हिस्सा लिया है, मेरे पास एक एक सदस्य के लिखित वक्तव्य हैं। विशेष तौर पर जीवन राय जी ने जो सुझाव दिये, उनको मैं विस्तार से कहता लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि मैं सारी बातों को यहां नहीं रख सकता।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : आप बाद में भेज दीजिएगा।

श्री शरद यादव : केवल एक बात कहता हूं कि जो डिबेट हुई है यह बेहतर डिबेट है और आप सबकी चिंता से मैं सहमत हूं। इस समस्या के समाधान के लिए प्लानिंग कमीशन में जो ग्रुप बना है, जो अनइम्प्लॉयमेंट को दूर करने का काम करेगा, उसके पास यह सारी डिबेट भेजने का काम मैं जरूर करूंगा जिससे इस बहस का नतीजा निकल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE ALL-INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) BILL, 2001

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, Dr. C. P. Thakur will move the motion for amendment of the All-India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. P. THAKUR): Sir, I move:-

> "That the Bill further to amend the All-India Institute of Medical Sciences Act, 1956, be taken into consideration."

Sir, actually this is a small Bill. It aims at correcting certain omissions, or you can say, mistakes; it may be a mistake in typing, or an omission of that type committed at that time in 1956. When the Act was designed, it was provided that the Institute would impart training in dentistry and dental colleges would be opened. But where they had to provide that degrees should be awarded, they had left BDS and they had also left